

RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
अक्टूबर
27
2025

- Key Point**
1. National News
 2. International News
 3. Govt. Mission, Apps
 4. Awards & Honours
 5. Sports News
 6. Economic News
 7. Newly Appointment
 8. Defence News
 9. Important Days
 10. Technology News
 11. Obituary News
 12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को मजबूत करना / Strengthening Governance through Blockchain Technology

संदर्भ:

भारत नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक को तेजी से अपना रहा है। इस पहल का उद्देश्य सुशासन को सुदृढ़ बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल भरोसे को मजबूत करना है। यह कदम सरकार और सार्वजनिक सेवाओं में अधिक दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

ब्लॉकचेन क्या है?

ब्लॉकचेन एक वितरित, पारदर्शी, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डिजिटल डेटाबेस है, जो एक लेजर (ledger) की तरह काम करता है।

इसमें किए गए लेन-देन (transactions) का रिकॉर्ड नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटरों पर सुरक्षित रहता है, जिसे बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इस वजह से ब्लॉकचेन तकनीक पर पूरा भरोसा और पारदर्शिता बनी रहती है।

ब्लॉकचेन के प्रकार:

1. सार्वजनिक ब्लॉकचेन:

- यह नेटवर्क सभी के लिए खुला होता है।
- कोई भी व्यक्ति इसमें रिकॉर्ड देख सकता है, ट्रांजेक्शन को सत्यापित (verify) कर सकता है और नए ब्लॉक जोड़ सकता है।
- इसका उपयोग Bitcoin और Ethereum जैसी क्रिप्टोकॉइन्स में किया जाता है।

2. निजी ब्लॉकचेन:

- यह एक अनुमति-आधारित (permissioned) नेटवर्क होता है।
- इसमें केवल चुने हुए सदस्यों को ही प्रवेश और कार्य करने की अनुमति होती है।
- डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और दक्षता (efficiency) बनाए रखने के लिए इसे सरकारी या बड़ी संस्थाओं में उपयोग किया जाता है।

3. संघीय या कंसोर्टियम ब्लॉकचेन:

- यह अर्ध-विकेन्द्रीकृत (semi-decentralized) नेटवर्क होता है।
- इसे कई संगठनों द्वारा मिलकर नियंत्रित किया जाता है।
- यह साझा डेटा प्रबंधन (shared data management) और सत्यापन के लिए उपयुक्त है।
- इसका उपयोग बैंकिंग, सप्लाई चेन और वित्तीय क्षेत्रों में किया जाता है।

4. हाइब्रिड ब्लॉकचेन:

- यह सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन का मिश्रण होता है।
- इसमें कुछ डेटा सार्वजनिक होता है जबकि संवेदनशील डेटा निजी रखा जाता है।
- इससे पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों बनी रहती हैं।

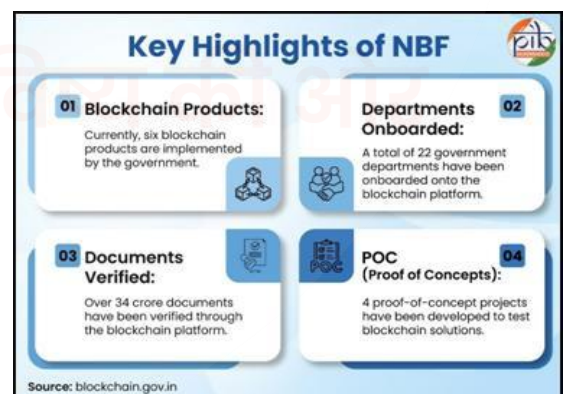


ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें:

नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (National Blockchain Framework - NBF), 2024: इसके मुख्य घटकों में विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टैक (Vishvasya Blockchain Stack), एनबीएफलाइट (NBFLite), प्रमाणिक (Praamaanik - ऐप सत्यापन के लिए अभिनव ब्लॉकचेन समाधान) और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल शामिल हैं।

नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क:

- विकसित करने वाला विभाग:** यह फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
- शुरुआत का वर्ष:** इसे वर्ष 2024 में ₹64.76 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ लॉन्च किया गया।



मुख्य उद्देश्य: NBF का उद्देश्य अनुमति-आधारित (permissioned) ब्लॉकचेन आधारित एप्लिकेशनों के विकास और क्रियान्वयन को तेज़ करना है।

- यह पहल भारत में एक सुरक्षित, पारदर्शी और विस्तारणीय डिजिटल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक **रणनीतिक कदम** है।

क्लाउड सीडिंग / Cloud Seeding

संदर्भ:

दिल्ली सरकार, आईआईटी कानपुर के सहयोग से, क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के माध्यम से कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) कराने के परीक्षण कर रही है, ताकि गंभीर वायु प्रदूषण (Air Pollution) से निपटा जा सके। यदि मौसम अनुकूल रहा, तो पहला पूर्ण पैमाने का संचालन 28 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच किए जाने की संभावना है।

हालिया परीक्षण और नियोजित संचालन:

- **परीक्षण उड़ान:** अक्टूबर 2025 में बुराड़ी क्षेत्र के ऊपर एक सफल परीक्षण उड़ान संचालित की गई। इस उड़ान का उद्देश्य विमान की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय (coordination) की जांच करना था।
- **संचालन अवधि:** इन उड़ानों को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच, मॉनसून के बाद के धुंध (smog) मौसम में संचालन की अनुमति दी गई है।
- **पहली कृत्रिम वर्षा:** पहली कृत्रिम वर्षा 29 अक्टूबर को की जाने की संभावना है, बशर्ते मौसम विभाग का बादल युक्त मौसम का पूर्वानुमान सही साबित हो।
- **तकनीकी सहयोग:** यह ₹3.21 करोड़ का संयुक्त प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच किया जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने सीडिंग मटेरियल विकसित किया है और इसके लिए संशोधित सेसना विमान का उपयोग किया जा रहा है।

क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding):

क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन (weather modification) तकनीक है, जिसमें रासायनिक पदार्थ (chemical substances) को हवा में छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा (rainfall) उत्पन्न की जाती है। ये पदार्थ क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लियाई (cloud condensation nuclei) का काम करते हैं।

क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लियाई: ये छोटे कण होते हैं, जिन पर जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाता है।

उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ:

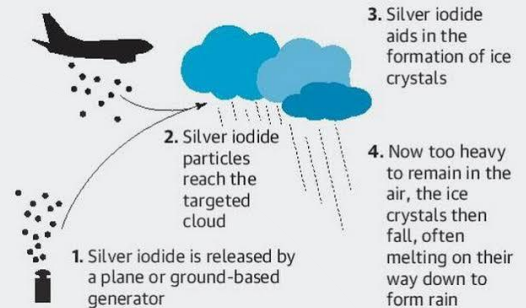
- सिल्वर आयोडाइड (Silver Iodide)
- पोटेशियम आयोडाइड (Potassium Iodide)
- ड्राई आइस (Dry Ice - ठोस कार्बन डाइऑक्साइड)
- लिक्विड प्रोपेन (Liquid Propane)

काम करने की शर्तें:

- हवा में पहले से पर्याप्त बादल होना चाहिए।
- लंबी और नमी वाली बादलों (tall, moist clouds) की आवश्यकता होती है।
- कम हवा की गति (low wind conditions) अनुकूल होती है।

प्रदूषण कम करना: कृत्रिम वर्षा वायु से धूल और प्रदूषक कणों को धोकर वातावरण को साफ करती है।

How cloud seeding works



क्लाउड सीडिंग के तरीके:

1. **हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग:** बादलों के निचले हिस्सों में नमक (salts) को विस्फोटकों (explosives) के माध्यम से छिड़का जाता है।
2. **स्टैटिक क्लाउड सीडिंग:** बादलों में सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल (silver iodide crystals) जैसी रसायनियों का छिड़काव किया जाता है।
3. **डायनामिक क्लाउड सीडिंग:** ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय प्रवाह (vertical air currents) को बढ़ावा देकर अधिक पानी को बादलों से होकर गुजरने दिया जाता है, जिससे अधिक वर्षा होती है।

क्लाउड सीडिंग की सीमाएँ:

1. **सूखे की समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर सकता:** यह केवल पानी की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा कर सकता है।
2. **सभी बादल उपयुक्त नहीं होते:** हर बादल से वर्षा उत्पन्न नहीं की जा सकती।
3. **नमी अनिवार्य है:** इसके लिए नमी युक्त बादलों (moisture-bearing clouds) का होना जरूरी है।
4. **असामान्य मौसम पैदा कर सकता है:** उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रूप से कम नमी वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से फ्लैश फ्लड (flash floods) का खतरा बढ़ सकता है।
5. **पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक:** क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थ विषैले होते हैं।
6. **वैश्विक गर्मी में योगदान:** इसमें प्रयुक्त रसायन ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) का स्रोत भी होते हैं।

अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर कार्यक्रम: भारत के वैश्विक व्यापार विश्वास को बढ़ावा देना / Authorized Economic Operator Programme: Boosting India's Global Trade Confidence

संदर्भ:

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने हाल ही में भारत के **लिबरलाइज्ड ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर (AEO) प्रोग्राम** की सराहना की है, जिसने **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

AEO प्रोग्राम के बारे में (About the AEO Programme):

Authorized Economic Operator (AEO) प्रोग्राम वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन (WCO) के SAFE Framework of Standards (FoS) के तहत संचालित होता है।

- यह एक वैश्विक पहल (global initiative) है जिसे जून 2005 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित और सुगम बनाना है।

भारत में AEO:

- भारत में यह योजना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) द्वारा लागू की गई है।
- यह वैश्विक मानकों पर आधारित है और कस्टम अधिकारियों और व्यापारिक हितधारकों के बीच भरोसेमंद साझेदारी (trust-based partnerships) को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है।

शुरुआत (Launched):

- AEO प्रोग्राम का **पायलट वर्ष 2011** में शुरू हुआ और **2016 में इसका विस्तार** किया गया।
- इसने भारत के पहले Accredited Client Programme (ACP) को समाहित करके एकीकृत ढांचा (unified framework) तैयार किया।

AEO के उद्देश्य (Objectives of AEO):

- सप्लाई चेन सुरक्षा बढ़ाना (Enhance supply chain security)** और सामान की गति को तेज करना।
- व्यापारियों और लॉजिस्टिक ऑपरेटरों में अनुपालन संस्कृति (compliance culture)** को बढ़ावा देना।
- व्यापार को सरल बनाना (Trade simplification)**, जबकि उच्च जोखिम वाले संस्थाओं पर प्रवर्तन (enforcement) पर ध्यान केंद्रित करना।
- भारत के निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय पहचान सुधारना, Mutual Recognition Agreements (MRAs) के माध्यम से अन्य देशों के साथ।

संरचना और कार्यान्वयन:

- यह प्रोग्राम स्वैच्छिक है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े सभी संस्थाओं (importers, exporters, customs brokers, logistics providers, custodians, warehouse operators) के लिए खुला है।
- प्रोग्राम का प्रबंधन Directorate of International Customs (CBIC) करती है।

- AEO प्रमाणपत्र (AEO certification) प्रदान करने से पहले विस्तृत अनुपालन ऑडिट (detailed compliance audit) किया जाता है।

AEO प्रोग्राम के लाभ:

- तेज़ कस्टम्स क्लीयरेंस:** Direct Port Delivery (DPD) और Entry की सुविधा आयात/निर्यात माल (import/export cargo) के लिए।
- स्थगित शुल्क भुगतान:** AEO-T2 और T3 धारकों के लिए कस्टम्स ड्यूटी में लचीलापन।
- वैश्विक मान्यता:** भरोसेमंद व्यापारियों के लिए Mutual Recognition Agreements (MRAs) के माध्यम से पारस्परिक लाभ।
- व्यापार अनुपालन में सरलता:** Standard Input Output Norms (SION) का स्वयं-घोषणा।
- वित्तीय और समय की बचत:** तेज़ रिफंड, कम निरीक्षण और प्राथमिकता प्राप्त प्रोसेसिंग।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) –

क्या है WTO: यह एक अंतरसरकारी संगठन है जो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमबद्ध और सुगम बनाता है, और यह सदस्य देशों की सहमति पर आधारित होता है।

- स्थापना:** 1 जनवरी 1995 को मेराकेस समझौते के तहत; GATT (1948) का उत्तराधिकारी।
- उत्पत्ति:** 1986-94 के उरुग्वे राउंड वार्ताओं का परिणाम; GATT के नियमों को विस्तारित करके इसमें माल, सेवाएँ और बौद्धिक संपदा (IP) शामिल की गई।
- मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्जरलैंड – दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन।
- सदस्य देश:** 166 (भारत संस्थापक सदस्य), जो वैश्विक व्यापार का 98% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।
- महत्व:** यह अकेला अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार नियमों से संबंधित है।



2025 ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स / 2025 Global Multidimensional Poverty Index

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) ने मिलकर 2025 का वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index - MPI) जारी किया है।

2025 ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पवर्टी इंडेक्स:

ग्लोबल MPI 100+ विकासशील देशों में **गंभीर बहुआयामी गरीबी (acute multidimensional poverty)** को मापता है।

यह स्वास्थ्य (health), शिक्षा (education), आवास (housing), स्वच्छता (sanitation) और ऊर्जा की पहुँच (energy access) सहित कई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलस (SDGs) में लोगों की कमी को दर्शाता है।

मुख्य विवरण:

- **विकसित करने वाले (Developed by):** UNDP और OPHI, University of Oxford
- **शुरुआत (Launch):** 2010
- **उद्देश्य (Purpose):** आय पर आधारित माप से आगे जाकर गरीबी को **स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** जैसे कई संकेतकों के आधार पर मापना।
- **गरीबी की पहचान:** यदि कोई व्यक्ति वज़नी संकेतकों में कम से कम एक-तिहाई (one-third) से वंचित है, तो उसे "बहुआयामी गरीब माना जाता है।
- **इंडेक्स (Index):** MPI 0 से 1 के बीच होता है, और अधिक मान (higher value) अधिक गरीबी को दर्शाता है।

नई विशेषता – 2025 संस्करण:

- पहली बार यह रिपोर्ट गरीब आबादी को चार प्रमुख **जलवायु खतरों (climate hazards)** के प्रति उनकी संवेदनशीलता के साथ मैप करती है:
 1. उच्च तापमान (High Heat)
 2. सूखा (Drought)
 3. बाढ़ (Floods)
 4. वायु प्रदूषण (Air Pollution)

ग्लोबल MPI रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष:

1. वैश्विक गरीबी आँकड़े (Global Poverty Statistics)

- 109 देशों में 6.3 अरब लोगों में से **1.1 अरब (18.3%)** लोग **गंभीर बहुआयामी गरीबी** में रहते हैं।
- अधिकांश लोग युवा, ग्रामीण (rural) और कम मानव विकास वाले देश में रहते हैं।

2. भारत में बहुआयामी गरीबी (Multi-dimensional Poverty in India)

- भारत में गरीबी **55.1% (2005–2006)** से घटकर **16.4% (2019–2021)** हो गई।
- भारत के कई क्षेत्र **गंभीर गरीबी, उच्च तापमान (high heat), बाढ़ (flooding), और वायु प्रदूषण (air pollution)** जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

3. गरीबी और जलवायु का संबंध:

- जलवायु संकट अधिक **बारंबार और तीव्र (frequent and intense)** हो रहे हैं।
- 2022 में **32 मिलियन लोग (32 million)** विस्थापित हुए।
- यदि मजबूत जलवायु नियंत्रण नहीं किया गया, तो **सर्वाधिक गरीबी (extreme poverty)** 2050 तक लगभग **दोगुनी (double)** हो सकती है।

4. उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:

- **309 मिलियन गरीब लोग** ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ **तीन या चार जलवायु खतरे और गंभीर गरीबी** का मेल है।
- इन्हें कम संपत्ति और सीमित सामाजिक सुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

5. आय स्तर के अनुसार MPI: दुनिया के गरीबों में से लगभग दो-तिहाई (64.5%) मध्य-आय वाले देशों में रहते हैं।

- **निम्न-मध्य आय वाले देश (Lower-middle-income):** 55.5%
- **उच्च-मध्य आय वाले देश (Upper-middle-income):** 9%

6. सामान्य अभाव: प्रमुख अभाव में शामिल हैं:

- स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की कमी: 970 मिलियन
- पर्याप्त आवास की कमी: 878 मिलियन
- स्वच्छता की कमी: 830 मिलियन
- कुपोषण: 635 मिलियन
- स्कूल न जाने वाले बच्चे: 487 मिलियन

7. MPI में असमान प्रगति:

- 88 देशों में से 76 देशों ने **MPI में कमोबेश सुधार** देखा है।
- **Benin** ने सबसे तेज **संपूर्ण कमी** दर्ज की (2017–2018 से 2021–2022)।
- इसके बाद **Cambodia (2014–2021–2022)** और **Tanzania (2015–2016 से 2022)** का स्थान है।



RBI ने अधिग्रहण के लिए 70% वित्तपोषण का प्रस्ताव / RBI proposes 70% financing for acquisitions

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक **ड्राफ्ट सर्कुलर** जारी किया है, जिसमें बैंकों के पूंजी बाजार और कॉर्पोरेट अधिग्रहणों में जोखिम को प्रबंधित करते हुए क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीमाएँ निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्य प्रस्ताव (Key Proposals):

1. पूंजी बाजार में जोखिम (Capital Market Exposure):

- बैंकों का कुल **exposure** (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष - जैसे फंड, गारंटी के माध्यम से) **Tier-1 capital** का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- Tier-1 capital** में शामिल हैं:
 - इक्विटी (Equity)
 - संचित लाभ (Retained Earnings)
 - कुछ ऐसे उपकरण (instruments) जो नुकसान सहन कर सकते हैं।

2. अधिग्रहण वित्तपोषण (Acquisition Financing / Loans for Buying Companies):

- अधिग्रहण वित्तपोषण पर बैंकों का **exposure** Tier-1 capital का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- बैंक अधिग्रहण सौदे का अधिकतम **70% तक** वित्तपोषण कर सकते हैं; शेष 30% अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा होना चाहिए।
- केवल **सूचीबद्ध कंपनियाँ (listed entities)** जिनकी **नेट वर्थ और लाभप्रदता (profitability)** पिछले तीन वर्षों में संतोषजनक हो, पात्र होंगी।
- लोन पूरी तरह **target company** के शेयरों से सुरक्षित (**fully secured**) होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बैंक पैसा वसूल कर सके।

3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए संशोधित जोखिम-भार दिशानिर्देश (Revised Risk-Weight Guidelines):

- अवसंरचना (infrastructure) लोन के लिए **संशोधित जोखिम-भार दिशानिर्देश** प्रस्तावित किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य **स्थापित परियोजनाओं (established projects)** के लिए लोन देने वाले NBFCs के **पूँजी आवश्यकता (capital requirement)** को कम करना है।

संदर्भ:

भारतीय वायु सेना (IAF) **Exercise Ocean Sky 2025** में भाग ले रही है, जो कि **स्पेनिश वायु सेना** द्वारा **गांडो एयर बेस, स्पेन** में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है।



अभ्यास के बारे में:

- यह अभ्यास आपसी सीखने, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने, हवाई युद्ध कौशल (air combat skills) को निखारने और मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग (defence cooperation) को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास में 50 से अधिक विमानों (aircraft) का हिस्सा है, जिनमें स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, भारत और अमेरिका शामिल हैं।
- भारत की तरफ से Su-30MKI फाइटर जेट इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

भारत-स्पेन रक्षा संबंधों का विकास:

- अगस्त 2025 में भारत को स्पेन के Seville स्थित Airbus Defence and Space सुविधा से 16 Airbus C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अंतिम खेप प्राप्त हुई।
- C-295 प्रोजेक्ट भारत में पहली निजी क्षेत्र की मिलिट्री एयरक्राफ्ट उत्पादन पहल है, जो Tata Advanced Systems Limited (TASL) और Airbus Spain की साझेदारी में है।
- इसके अलावा, वडोदरा, गुजरात में फाइनल असेंबली लाइन (Final Assembly Line) स्थापित की जा रही है, जहाँ भारत में बाकी के 40 में से 56 विमान बनाए जाएंगे।

GS FOUNDATION

For

UPSC & STATE PSC

◆ इतिहास ◆ अर्थव्यवस्था ◆ भूगोल
◆ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- ✓ रोज़ाना लाइव क्लासेस
- ✓ साप्ताहिक टेस्ट
- ✓ क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- ✓ लाइव डाउट सेशन
- ✓ रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE
VALIDITY
1 YEAR



FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND

INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH

COMBO OFFERS

COURSE FEE

~~₹4000/-~~

OFFER PRICE

₹2800/-

Course Validity
1 YEAR

एक निवेश समझदारी से..



BBK
Baaten Bazar ki

FUNDAMENTALS OF STOCK MARKET

LEARN HOW TO TRADE

Course fee

₹1999/-

COURSE
VALIDITY
1 YEAR



INVESTMENT की करो जीरो से शुरूवात



FOUNDATION COURSE OF MUTUAL FUND



Invest in Knowledge

Grow Your Wealth

Course fee

₹1999/-

COURSE
VALIDITY

1 YEAR



एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE



(FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- » Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- » Sectoral Investing
- » Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

FREE



SPECIAL BONUS

**COURSE VALIDITY
1 YEAR**

